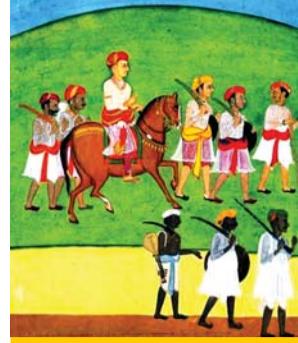


ARBIT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

"Ere we came back from Paniput..."

The battle is considered to have been one of the largest and most eventful, fought in the 18th century, and it had, perhaps, the largest number of fatalities in a single day reported in a classic formation battle between two armies.

Humans will soon be able to Mine on the Moon. But should we?

वेणुगोपाल हरियाणा में नई जाट “लीडरशिप” पनपाना चाहते हैं

**भूपेन्द्र सिंह हुड़ा की जगह रणदीप सिंह
सुरजेवाला को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त कर, इस पीढ़ी
परिवर्तन की शुरुआत करना चाहते हैं**

-रेणु मितल-

नई दिल्ली, 10 जनवरी। हरियाणा कांग्रेस टकराव की ओर बढ़ रही है। पुराने जाट नेतृत्व की जाट नया नेतृत्व लाने की लड़ाई शुरू हो गई है। इस्यु में हाल ही में हुये विधानसभा चारोंमें जीतकर आये 37 विधायकोंमें से 30 विधायक हरियाणा के सी.एल.पी. नेता भूपेन्द्र सिंह हुड़ा के नियंत्रणमें हैं। इसके साथ ही, पार्टी के 5 निवाचित लोकसभा संसदीयोंमें से 4 सांसद हुड़ा के साथ हैं। इनमें हुड़ा के पुरुषोंपर सिंह हुड़ा भी शामिल हैं।

समझा जाता है कि के.सी.वेणुगोपाल नये जाट नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को पी.सी.सी. अध्यक्ष बनाने वाले होंगे। इसका अर्थ यह होगा कि सी.एल.पी. नेता का पद किसी गैर-जाट नेता को मिलाया।

इस बालाक को पीढ़ी वेणुगोपाल के दो उद्देश्य हैं। पहली बात तो यह है कि वे हरियाणा में नया नेतृत्व चाहते हैं तथा

- स्वाभाविक ही है, भूपेन्द्र सिंह हुड़ा, इस पीढ़ी परिवर्तन के खिलाफ हैं और कांग्रेस के 37 विधायकोंमें से तीस पर हुड़ा का नियंत्रण है और यह ही स्थिति लोकसभा सदस्योंकी है। हरियाणा के पाँच संसदीयोंमें से चार हुड़ा कैम्प के हैं और इस कारण वेणुगोपाल की पीढ़ी परिवर्तन की योजना आसानी से क्रियान्वित होती नजर नहीं आ रही है।
- पर, वेणुगोपाल भी हार नहीं मान रहे हैं तथा सुरजेवाला को हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष बनाने के प्रयास उन्होंने छोड़ नहीं है।
- पीढ़ी परिवर्तन के अलावा वे सुरजेवाला को कर्नाटक से हरियाणा इसलिए भी लाना चाहते हैं कि कर्नाटक एक धनाद्यप्रदेश है, सुरजेवाला को वहाँ से हटाकर, वे अपने आदमी को कर्नाटकमें प्रभारी नियुक्त करना चाहते हैं। जैसा कि विदित ही है, सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी हैं।
- हुड़ा ने भी परोक्ष रूप से धमकी दे रखी है कि उन पर ज्यादा दबाव डाला गया, हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष का पद छोड़ने के लिये, तो वे पार्टी में विभाजन करा देंगे।

दूसरी ओर ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा चाहते हैं, हुड़ा, परिवर्तन की इस माँग पर विधानसभा चुनावोंके बाद, कांग्रेस जो देश के सर्वाधिक समय राज्योंमें से विचार करने के राजी नहीं हैं। एक ही तथा उस पद पर वे किसी संकेत को हाना करना चाहते हैं। संकेत देंदिया है कि अगर यहाँ पर ज्यादा खास व्याप्ति को लाना चाहते हैं। सुरजेवाला ए.एस.सी.सी. दबाव डाला गया तो वे पार्टी तोड़ने पर चुनावोंमें भाजपा से हार गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा में शिक्षा पर नोटिस जारी किये

नयी दिल्ली, 10 जनवरी। राजस्थान के प्राचीनकाल से विद्यालयोंमें बच्चों को राजस्थानी भाषा में देने के मामले में शिक्षा सुधूरी कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। पवा मेहता नाम के विधिक नोटिस कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है। पवा मेहता नाम के विधिक नोटिस कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है।

अदालत में पेश याचिका में बच्चोंको मातृभाषा में शिक्षा दिलवाने की मांग की है।

से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयोंमें बच्चोंको शिक्षा राजस्थानी भाषा राजस्थान में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है, जिससे साकार वर्षांसे लोग बोलते हैं, लेकिन अदालत ने यह प्रतिक्रिया करने के लिए एक विधिक नोटिस कोर्ट को नोटिस जारी किया है।

से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयोंमें बच्चोंको शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है, जिससे साकार वर्षांसे लोग बोलते हैं, लेकिन अदालत ने यह प्रतिक्रिया करने के लिए एक विधिक नोटिस कोर्ट को नोटिस जारी किया है।

से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयोंमें बच्चोंको शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है, जिससे साकार वर्षांसे लोग बोलते हैं, लेकिन अदालत ने यह प्रतिक्रिया करने के लिए एक विधिक नोटिस कोर्ट को नोटिस जारी किया है।

से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयोंमें बच्चोंको शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

को नोटिस जारी किया है, जिससे साकार वर्षांसे लोग बोलते हैं, लेकिन अदालत ने यह प्रतिक्रिया करने के लिए एक विधिक नोटिस कोर्ट को नोटिस जारी किया है।

से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयोंमें बच्चोंको शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

को नोटिस जारी किया है, जिससे साकार वर्षांसे लोग बोलते हैं, लेकिन अदालत ने यह प्रतिक्रिया करने के लिए एक विधिक नोटिस कोर्ट को नोटिस जारी किया है।

से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयोंमें बच्चोंको शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

को नोटिस जारी किया है, जिससे साकार वर्षांसे लोग बोलते हैं, लेकिन अदालत ने यह प्रतिक्रिया करने के लिए एक विधिक नोटिस कोर्ट को नोटिस जारी किया है।

से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयोंमें बच्चोंको शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

को नोटिस जारी किया है, जिससे साकार वर्षांसे लोग बोलते हैं, लेकिन अदालत ने यह प्रतिक्रिया करने के लिए एक विधिक नोटिस कोर्ट को नोटिस जारी किया है।

से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयोंमें बच्चोंको शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

को नोटिस जारी किया है, जिससे साकार वर्षांसे लोग बोलते हैं, लेकिन अदालत ने यह प्रतिक्रिया करने के लिए एक विधिक नोटिस कोर्ट को नोटिस जारी किया है।

से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयोंमें बच्चोंको शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

को नोटिस जारी किया है, जिससे साकार वर्षांसे लोग बोलते हैं, लेकिन अदालत ने यह प्रतिक्रिया करने के लिए एक विधिक नोटिस कोर्ट को नोटिस जारी किया है।

से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयोंमें बच्चोंको शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

को नोटिस जारी किया है, जिससे साकार वर्षांसे लोग बोलते हैं, लेकिन अदालत ने यह प्रतिक्रिया करने के लिए एक विधिक नोटिस कोर्ट को नोटिस जारी किया है।

से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयोंमें बच्चोंको शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

को नोटिस जारी किया है, जिससे साकार वर्षांसे लोग बोलते हैं, लेकिन अदालत ने यह प्रतिक्रिया करने के लिए एक विधिक नोटिस कोर्ट को नोटिस जारी किया है।

से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयोंमें बच्चोंको शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

को नोटिस जारी किया है, जिससे साकार वर्षांसे लोग बोलते हैं, लेकिन अदालत ने यह प्रतिक्रिया करने के लिए एक विधिक नोटिस कोर्ट को नोटिस जारी किया है।

से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयोंमें बच्चोंको शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।

को नोटिस जारी किया है, जिससे साकार वर्षांसे लोग बोलते हैं, लेकिन अदालत ने यह प्रतिक्रिया करने के लिए एक विधिक नोटिस कोर्ट को नोटिस जारी किया है।

से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयोंमें बच्चोंको शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है।